IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES
ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved Journal UGC CARE Listed (Group-I) Volume 11, Issue 06, Jun 2022

संसाधनो का उपर्युक्त प्रयोग एवं नियोजन

सुनील कुमार
शोधार्थी
टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर

डॉ0 धीरज यादव
सहायक आचार्य (भूगोल विभाग)
टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर

प्रस्तावित शोध की भूमिका

नियोजन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एंव पर्यावरणीय गुणात्मकता को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन है। यद्यपि नियोजन का अस्तित्व एक नवीनतम विषय के रूप मे है तथापि उसका विषय क्षेत्र अत्यन्त व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि यह एक अग्रणी विषय के रूप में उभरकर सामने आया है। जिसमें मुख्यतः मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अन्तर्गत मानवीय पर्यावरण के विकास एवं सामाजिक संसाधनों के उपयुक्त प्रयोग पर नवीन विधियों एवं तकनीकों के क्रियाकलापों को महत्व प्रदान करने के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक असमानताओं, असंतुलन एवं सामाजिक अन्याय के विश्लेषण पर भी प्रकाश डाला जाता है और सामाजिक कल्याण हेतु इन असमानताओं को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं।

वर्तमान समय में नियोजन वास्तव में एक सार्वभौमिक प्रगति का उद्घोष है। आज के प्रगतिशील युग में, अवाधगति से बढ़ती हुई सामाजिक समस्याओं के निदान का प्रमुख साधन नियोजन है। यही कारण है कि इसे विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर सहर्ष स्वीकार किया जाता है ताकि सूक्ष्म स्तर पर समाज की छोटी इकाइयों की आकांक्षाओं को सरलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके और आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा अक्षुण्य रहे। इसके लिए नियोजक का प्रथम कर्त्तव्य यह होना चाहिए कि वह जिस क्षेत्र के लिए योजना का निर्माण करे, उसके क्रियान्वयन से पूर्व उस क्षेत्र के भौतिक स्वरूप व अन्य सामाजिक परिस्थितियों का भलीभांति सर्वेक्षण कर ले जो कि वहां के मानवीय पर्यावरणीय अन्तर्सम्बन्धों का परिणाम है।

नियोजन प्रक्रिया के विकास में भूगोलविदों का महत्वपूर्ण योगदान है। केवल भूगोलवेत्तर ही है, जिनका स्थानिक संगठनों तथा स्थानिक विश्लेषण की विशिष्ट तकनीकों पर स्वामित्व है। साथ ही यह मानव, समाज एवं पर्यावरण के मध्य अंतर्क्रियाओं में समाहित

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

विभिन्न समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से एक बेहतर स्थिति में है क्योंकि ये स्थानीय विश्लेषणों की विशिष्ट शिक्षण कला से परिचित होते है। इनका योगदान वास्तव में न केवल सम्पूर्ण स्थानीय असमाताओं एवं अन्यायों की व्याख्या तथा विवरण में ही सुधारात्मक है बल्कि मानवीय प्रसंगौचित्तता हेतु बदलाव में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

नियोजन की संकल्पना (Concept of Planning)

नियोजन के द्वारा मानव का सामाजिक एंव आर्थिक विकास होता है इस विकास के अन्तर्गत प्रकृति के द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ साधनों का उपयोग कर मानव इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। जिसमें दिये गये या प्राप्त हुए तर्को के द्वारा मानव अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए जनता के द्वारा निर्धारित नियम को शामिल कर भविष्य के लिए एक ठोस योजना प्रस्तुत करता है। संसाधनों को बहुत ही कम मात्रा में खर्चकर अधिकाधिक समस्याओं का समाधान की नियोजन हैं।

इस प्रकार नियोजन को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि यह एक संगठित, तार्किक एवं सतत् प्रयास है, जिसके द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन किया जाता है।

प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना (Concept of Regional Planning)

प्रादेशिक नियोजन को एक विशेष प्रकार के वैज्ञानिक अनुबंध के रूप में लेना चाहिए। सर्वप्रथम यह भविष्योन्मुख सामाजिक लक्ष्यों तथा क्षेत्रीय प्रबन्धों के बीच सम्बन्धों को परिलक्षित करता है। परियोजनाओं की संतुलित एकता के संदर्भ में अत्यधिक उपयुक्त ढांचों के निर्माण से सम्बन्धित है। इस प्रकार की विस्तृत प्रादेशिक योजनाएं–ग्रामीण निर्माण योजनाओं के पुनर्निमाण, उद्योगों की अवस्थिति, ऐसे क्षेत्रों के लिए जिनमें विकास योग्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और महानगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रयोग किया जाना आवश्यक है (फ्रीडमैन, 1972)। वस्तुतः प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना स्थैतिक नहीं है बल्कि क्षेत्र एवं योजना दोनों ही रूपों में गत्यात्मक है। यह मानवीय एवं प्राकृतिक सम्बन्धों के बदलते रिश्तों तथा क्षेत्रीय आधारों पर परिवर्तनीय है। प्रादेशिक नियोजन क

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

विधियां तथा उद्देश्य चालीस–पचास वर्षों के बाद ठीक उसी प्रकार आज जैसे नहीं रहेंगे। जैसे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आज भी समान नहीं है।

प्रस्तावित शोध के सोपान

विकास योजना विधि समूह से लघु–स्तरीय निर्णयों पर आधारित होती है ताकि राष्ट्रीय योजना नीति का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन किया जा सके। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि अभी तक इनमें से किसी भी विधि ने विकास योजना के लिए समुचित मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया है। वास्तव में ये गरीबी के कुछ पहलुओं को ही स्पर्श कर सकी हैं। किन्तु उसी समय सभी पहलुओं को स्पर्श करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी हैं जबकि सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है कि सभी समस्याओं का एक साथ निराकरण किया जाए। अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि नियोजन नीतियों का निर्धारण लोगों की बुनियादी, आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाए। जिसमें मानव कल्याण प्रमुखतः गरीब वर्गों के जीवन स्तर के उत्थान पर बल दिया जाए। साथ ही लाभ से वंचित एवं पिछड़े हुए लोगों की निर्धनता को दूर करने एवं उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने तथा आधारभूत बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए योजनाओ ं का निर्माण किया जाए। साथ ही आर्थिक प्रगति पर विशेष जोर दिया जाए जिसका माध्यम नगरीय औद्योगीकरण से लेकर समन्वित ग्रामीण विकास विधि हो तथा उपलब्ध सभी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकाधिक मात्रा में उपयोग करने के लिए योजना के सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

प्रस्तावित शोध का महत्व

लघु–स्तरीय नियोजन किसी क्षेत्र के विकास की संतुलित एवं सम्बद्ध रूपरेखा प्रस्तुत करता है। समाज के विभिन्न खण्डों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार की गई कार्य योजना का उद्देश्य स्थानीय प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग करना है जिससे ग्रामीण–निर्धनों को रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इस विधि में योजना निर्माण एवं कार्यान्यवन में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

कृषि पर आधारित शहरीकरण को विकसित करने की नई विचार प्रणाली में जैसा कि निम्न क्रम के केन्द्रों के योगदान के अन्तर्गत उम्पादन संसाधित करना एवं विपणन को प्रदान करने की कृषि पर आधारित विधि को एग्रोपोलिटन उपागम कहा जाता है (शर्मा 984)। जॉन फ्रीडमैन द्वारा प्रतिपादित यह एक स्थानीय संगठनों का वैकल्पिक प्रतिरूप है। जो कि नगरीय औद्योगिक विधियों की समालोचना के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है। इस सिद्धान्त के अनुसार विकास पारिस्थितिकीय सीमाओं पर आधारित होना चाहिए, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ग्रामीण विकास की येाजना विकेन्द्रीकृत होनी चाहिए तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी योजनाएं सहभागितायुक्त तथा स्थानीय परिस्थितियों से गहराई से सम्बद्ध होनी चाहिए (मिश्रा, 1973)। इस नई संयोजना को लागू करने के लिए कृषि पर आधारित स्थानिक नीति को अपनाया जाना चाहिए। इस विधि का उद्देश्य विशिष्ट ग्रामीण पर्यावरण के अनुसार शहरीकरण के तत्वों के द्वारा ग्रामीण परिवेश में परिवर्तन लाना है। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण लोगों को उनके खेत खलिहानों में शहरीय वातावरण का प्रादर्श प्रस्तुत कर, वे जहां हैं, वहीं रहने के लिए प्रोत्साहित करना है बजाय कि ग्रामीणों को शहरों की ओर आने हेतु प्रोत्साहित करें। इसके द्वारा यह सुझाव प्रस्तुत किया जाता है कि सामाजिक अन्तर्क्रियाओं का यह सिद्धान्त एक गांव से लेकर अनेक गांवो तक होगा ताकि विस्तृत रूप में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक एग्रोपोलिटन भू भाग का निर्माण किया जा सके।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य

1. विकास केन्द्रों की पहचान करना, जो कि विकास क्रियाकलापों की प्रक्रिया को नियमित एवं विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

2. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की सम्भाव्यताओं का मूल्यांकन करना तथा विकास एवं रोजगार के सुअवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का अनुरेखण किया गया है।

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

3. कमजोर वर्गों के बीच आय के अंतर को कम करने तथा गरीबी रेखा से ऊंचे उठने में उनकी सहायता करने वाले उपयोगी जीवन आश्रय देने वाले उत्पादक कार्यक्रमों की पहचान की गई है।

4. क्षेत्रीय आय एवं रोजगार को बढ़ाने हेतु अधिकतम विकास सम्भावनाओं का उपयोग करना।

प्रस्तावित शोध का निष्कर्ष

विकास ध्रुव केन्द्र से बाहर की ओर जाने वाली तथा केन्द्र की ओर आने वाली शक्तियों के साथ एक आदर्श आर्थिक स्थान का सूचक हैं। इस संकल्पना के अनुसार एक ही समय में सर्वत्र एक समान विकास नहीं होता है। यह वृद्धि, तीव्रता एंव विस्तार लिए विभिन्न दिशा मार्गों में विविध प्रयासों के परिणाम स्वरूप विकास केन्द्र पर होती है। यह विधि कुटीर एवं लघु उद्योंगों के विकास को प्रोत्साहित करती है तथा लघु औद्योगिक क्षेत्रों एवं उनके औद्योगिक विकास पर भी बल देती है। कुछ देशों में इस विधि को महानगरीय शहरों की वृद्धि को कम करने के लिए अपनाया गया है। लेकिन यह विधि सफल नहीं रही। यह वृहद एवं लघु खण्डों को जैविक सम्बद्धता प्रदान करने में एक प्रकार से विफल रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Adams, J.S. and Crould, P., (1971): Spatial Organization, The Geographer,s veiw of the word, New Jersey.
2. Agrawal, P.C. and Khan,Z.T.(1983): Spatial Analysis of the Level of Regional Development in Madhya Pradesh, Modern Geographical Trenda(ed)Praduman Panday.
3. Aziz. A,(1983): Studies in Block Planning, Concept Publishing Company, New Delhi.
4. Bhatt, L.S.(1972): Regional Planning, Concept Publishing Company, New Delhi,
5. Bhatt, L.S.(1976):Micro Level Planning-A Case Study of Kernal Area Haryana(India), New Delhi.